



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]  
No. 23]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 1969 (जेन्डा 17, 1891)  
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 1969 (JYAISTHA 17, 1891)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### नोटिस (NOTICE)

नीचे लिखा भारत का असाधारण राजपत्र 26 अप्रैल 1969 तक प्रकाशित किया गया है :—

The undermentioned *Gazette of India Extraordinary* was published up to the 26th April 1969 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबंधक, सिविल लाइन्स दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।  
मांग-पत्र प्रबंधक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय-सूचि (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	पृष्ठ 479	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . . . .	पृष्ठ 2154
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	605	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . . . . .	217
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	37	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .	541
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	525	भाग III—खंड 2—एकस्य कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें . . . . .	207
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . .	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .	61
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . . . .	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . . .	329
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . . .	1442	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . . . . .	99
		पूरक संख्या 23—	
		31 मई 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट . . . . .	961
		10 मई 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े . . . . .	975
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	Page 479	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . .	Page 2154
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	605	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . . . . .	217
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence . . . . .	37	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Sub-ordinate Offices of the Government of India . . . . .	541
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	525	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta.. . . .	207
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	61
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . . . .	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	329
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . .	1442	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	99
		SUPPLEMENT No. 23—	
		Weekly Epidemiological Reports for week-ending 31st May 1969 . . . . .	961
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 10th May 1969 . . . . .	975

## भाग I—खण्ड 1

## PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

## राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1969

सं० 27-प्रेज/69—राष्ट्रपति प्रादेशिक सेना के निम्नांकित आयुक्त अधिकारी को सराहनीय सेवा के लिये “प्रादेशिक सेना अलंकृष” प्रदान करते हैं:—

मेजर इन्द्र चन्द्र घोष, टी० ए० (एम०)-1012, आर्मी मेडिकल कोर।

दिनांक 28 मई 1969.

सं० 31-प्रेज/69—शुद्धि पत्र—दिनांक 5 नवम्बर, 1966 के भारतीय राजपत्र के भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 76-प्रेज/66, दिनांक 27 अक्टूबर, 1966 में शुद्धि करने हेतु:—

(क) पृष्ठ 718 पर

## (1) क्रम संख्या 52

वास्ते: “एन० वाई० ए० नायब रिजालदार जर्नेल सिंह, 4 हास”

पढ़े: “1007292 नायब रिजालदार जर्नेल सिंह 4 हास” (मरणोपरान्त)”

## (2) क्रम संख्या 60

वास्ते: “7015630 दफादार जगदीश लाल, 4 हास”

पढ़े: “7015630 हवलदार जगदीश लाल, ई० एम० ई०”

## (3) क्रम संख्या 90

वास्ते: “1024387 सवार चन्चल सिंह, 4 हास”

पढ़े: “1024387 सवार चन्चल सिंह, 4 हास” (मरणोपरान्त)”

## (ख) पृष्ठ 725 पर

क्रम संख्या 601

वास्ते: “लेफ्टिनेन्ट कर्नल शान्तिप्रिय गंगूली (आई० सी०-3652)”

पढ़ें: “लेफ्टिनेन्ट कर्नल शान्तिप्रिय गंगूली (आई० सी०-3653)”

ब० जे० मोर,

राष्ट्रपति के उप सचिव।

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1969

सं० 28-प्रेज/69—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

## अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चन्द्र धर बाजपेयी

पुलिस उप-निरीक्षक

रामपुर, उत्तर प्रदेश।

(स्थानापन्न)

## सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

15/16 अगस्त, 1965 की रात को सिविल लाइन्स, रामपुर में एक हथियार बेचने वाले की दुकान में चोरी हो गयी थी जिसमें कई बन्दूकें तथा कारतूस चुरा लिये गये थे। अपराधियों को तलाश करने के लिए सभी थानों तथा बाहरी-चौकियों द्वारा पुलिस-दल भेजे गये। अब इनमें से एक पुलिस दल, जिसमें श्री सी० डी० बाजपेयी, एक अन्य पुलिस उप-निरीक्षक तथा दो कांस्टेबल थे, दो साइकिल रिक्शों में जा रहा था तो उन्होंने दो आदमियों को सन्देहजनक परिस्थितियों में सड़क के निकट छुपे हुए देखा। श्री बाजपेयी ने संदिग्ध व्यक्तियों को चुनौती दी जिन्होंने श्री बाजपेयी तथा उनके दल पर शीघ्र गोली चला दी। इनमें से एक गोली श्री बाजपेयी के बगल, छाती तथा बाजू के अगले भाग में लगी तथा वे बुरी तरह घायल हो गये। दूसरी गोली रिक्शा चालक के पेट में लगी जिससे उसकी घटना-स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। घातक हमले तथा अपनी चोटों की बिल्कुल परवाह न करते हुये श्री बाजपेयी ने अपने आदमियों सहित अपराधियों पर हमला कर दिया और स्वयं एक से जूझ गये। यद्यपि उन्हें कुछ और चोटें लगी फिर भी वे उसे गिरफ्तार करने में सफल हुये। दूसरा अपराधी भी बाद में पकड़ लिया गया।

सशस्त्र अभियुक्तों से मुठभेड़ में श्री चन्द्र धर बाजपेयी ने उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम

4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 अगस्त, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 29-प्रेज/69—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

#### अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रहलाद राम,  
सहायक कमांडेंट,  
उरी बटालियन,  
राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी।

#### सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

सितम्बर, 1965 को श्री प्रहलाद राम को राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में सांचू की भारतीय चौकी पर पुनः कब्जा करने के लिये तैनात किया गया था, जिसे पाकिस्तानी सेनाओं ने युद्ध-विराम के पश्चात् लुक-छिप कर अपने कब्जे में कर लिया था। 30 सितम्बर, 1965 को प्राप्त: ही श्री प्रहलाद राम ने उक्त चौकी पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी सेनाएं खाईयों में और लाभप्रद स्थिति में थीं। उन्होंने बालू के टीलों पर कब्जा कर लिया था, जिनकी कगार-सदृश ढलानें थीं और आक्रमण के समय उन पर चढ़ना बहुत कठिन था। पाकिस्तानी सेनाओं ने नौ घंटे तक सक्त मुकाबला किया। किन्तु श्री प्रहलाद राम ने कई बार आक्रमण किये और वे हमेशा सबसे आगे रहे। श्री प्रहलाद राम की टुकड़ी तथा पाकिस्तानी सेनाओं के बीच हाथापाई के बाद अन्ततः पाकिस्तानी सेनाके पांव उखड़ गये। सात पाकिस्तानियों को बन्दी बना लिया गया तथा बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और अन्य उपकरण कब्जे में लिये गये।

सारे आक्रमणों के दौरान श्री प्रहलाद राम सब से आगे रहे और उन्होंने अपनी विशिष्ट वीरता, कर्तव्य परामर्शता एवं उच्च कोटि के नेतृत्व से अपनी टुकड़ी को विजयी बनाया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 सितम्बर, 1965 से दिया जायेगा।

सं० 30-प्रेज/69—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

#### अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सोनम बागंदी लामा,  
पुलिस निरीक्षक,  
डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ब्रांच,  
दार्जिलिंग।

(स्वर्गीय)

#### सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

24 मई, 1967 को सूचना मिली कि वण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, को तोड़ कर नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत बाराक्षारजोट नामक स्थान पर लोगों को उपद्रव करने के लिये एकत्रित किया जा रहा था। यह सूचना मिलते ही नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन के कमान-अधिकारी उपलब्ध अधिकारियों एवं सिपाहियों को साथ लेकर उस गांव की ओर चल पड़े। धनुष, बाण एवं अन्य घातक हथियारों से लैस 300-400 आदमियों के

समूह को देखकर नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन से कुमुक बुलाई गई जो सोनम बागंदी लामा, निरीक्षक के नेतृत्व में आ पहुंची। श्री लामा के कमान अपने हाथ में ली तथा जन-समूह को तितर-बितर करने के लिये उनके विरुद्ध बल प्रयोग करने से पूर्व इन्हें चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि पुलिस दल के आगे बढ़ने से जन-समूह मार-पीट करने के लिये भड़क सकता है। अतएव दूसरे पक्ष को बिना उकसाये ही रक्तपात को रोकने के लिये पुलिस निरीक्षक श्री बागंदी लामा जन-समूह की ओर आगे बढ़े और उनके पीछे-पीछे नक्सलवाड़ी पुलिस स्टेशन के कमान-अधिकारी तथा दो उप-निरीक्षक भी गये। इन में से कोई भी सशस्त्र न था। जन-समूह में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही थे। पुलिस निरीक्षक तथा उसके दल को अपनी और आता देखकर जन-समूह के पुरुष सदस्य वहां से अलग कुछ दूरी पर हट गये। निरीक्षक ने शान्तिपूर्ण ढंग से स्त्रियों के समूह को समझाया कि निषेधात्मक आदेशों के विपरीत इस प्रकार एकत्रित होना अच्छी बात नहीं है। उसके फलस्वरूप वह समूह तितर-बितर होने लग गया। जब यह हो रहा था, पुरुष सदस्य निषेधाज्ञा की परवाह न करके अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे। श्री लामा ने उनके पास जाकर उनसे भी शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाने के लिये आग्रह करने का निश्चय किया परन्तु ज्यों ही वह उनकी ओर बढ़े, उन लोगों ने उन पर तीर मारने आरम्भ कर दिये। इससे पूर्व कि मुख्य पुलिस दल उन विद्रोहियों को इस अकारण किये हुए निर्दयतापूर्ण कार्य से रोकता श्री लामा को चार तीर लग चुके थे। वह अचेत होकर गिर पड़े और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी।

2. श्री सोनम बागंदी ने जन-समूह को निश्शस्त्र एवं शान्तिपूर्ण तरीके से काबू में लाने में अदम्य साहस तथा चतुराई का परिचय दिया और रक्तपात को बचाने के हार्दिक प्रयत्न में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे डाली।

3. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1967 से दिया जायेगा।

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव

#### समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 1969

#### संकल्प

सं० एफ० 1-14/69-एस० डब्ल्यू-3—समाज कल्याण विभाग के दिनांक 22 अप्रैल 1969 के संकल्प संख्या एफ० 1-16/69-एस० डब्ल्यू-3 के अनुवर्तन में भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामान्य निकाय में सहर्ष नियुक्त करती है:—

1. श्रीमती एल० आर० विश्वास (उत्तर प्रदेश)
2. श्रीमती संध मित्रा चेटर्जी (त्रिपुरा)
3. श्रीमती कुसुमताई वानखेडे (महाराष्ट्र)
4. श्रीमती इन्दुबाला सुखाड़िया (राजस्थान)

5. प्रा० राजाराम शास्त्री (समाज कल्याण प्रशासक)  
6. डा० (श्रीमती) सी० पर्वधम्भा (समाज वैज्ञानिक)।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सभी सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. योजना आयोग।
6. मंत्री परिषद् सचिवालय।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय/प्रधानमंत्री सचिवालय।
8. प्रेस सूचना ब्यूरो।
9. केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, नई दिल्ली।
10. कम्पनी कार्य विभाग।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी ला बोर्ड, कानपुर।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली '(50 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो।

बी० एस० रामदास, उप सचिव

### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मई, 1969

### संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मई, 1969

सं० 8/2/69-हिन्दी-2—इस मंत्रालय के तारीख 5 सितम्बर, 1967 के संकल्प संख्या 8/2/67-हि० सं० सं० के अधीन गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति में श्री त्रिगुण सेन और श्री के० के० शाह के स्थान पर भारत सरकार डा० बी० के० आर० बी० राव, शिक्षा व युवक सेवाओं के मंत्री और श्री सत्यनारायण सिन्हा सूचना, प्रसारण व संचार मंत्री को सदस्यों के रूप में सहर्ष नियुक्त करती है।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सब राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय; प्रधान मंत्री सचिवालय; योजना आयोग; नियंत्रक और महालेखा परीक्षक; महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली; लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाय।

प्रेमनाथ धीर, उप-सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 मई, 1969

सं० 5/22/69-के० से० (1)—5 अप्रैल 1969 के भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में इस मंत्रालय की 5 अप्रैल 1969 की अधिसूचना संख्या 5/22/69-के० से० (1) के अन्तर्गत प्रकाशित, दिसम्बर 1969 में संघ लोक आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिए एक सीमित विभागीय परीक्षा के नियमों में :—

- (1) नियम 4 के नीचे टिप्पण-1 का द्वितीय उप-परिच्छेद निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय :—

तथापि यह बात उस सहायक/आशुलिपिक पर लागू नहीं होती जो संवर्ग-वाह्य पद पर नियुक्त किया गया हो या 'स्थानान्तरित' रूप में अन्य सेवा में नियुक्त हो और, यथास्थिति, सहायक/आशुलिपिक ग्रेड में ग्रहणाधिकार (लियन) न रखता हो।

- (2) उपर्युक्त नाम के नियमों के नियम 13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय :—

“13. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र के बाद, या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या जो किसी संवर्ग-वमह्य पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और, यथास्थिति, सहायक/आशुलिपिक ग्रेड में ग्रहणाधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तथापि, यह उस सहायक/आशुलिपिक पर लागू नहीं होता जो, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के किसी संवर्ग-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो”।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

### पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा वातु मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 1969

### संकल्प

सं० 22(13)/68-ओ० आर०—पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) के संकल्प संख्या 22(13)/68-ओ० आर० दिनांक 20 अप्रैल, 1968 की कंडिका (पैरा) 5 का, जिसका इसी संख्या के संकल्पों दिनांक 30 जुलाई, 1968, 23 नवम्बर 1968 तथा 31 जनवरी, 1969 द्वारा संशोधन किया गया था, संशोधन किया जाये और निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

“आयोग 31 जुलाई 1969 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सारे मंत्रालयों/विभागों, बिहार सरकार और अन्य सभी, जो इससे सम्बन्धित हों को भेजी जाए।

**संकल्प**

सं० 101/12/68-पी० पी० डी०—पेट्रोलियम और रसायन (पेट्रोलियम विभाग) के संकल्प संख्या 101(22)/68-पी० पी० डी० दिनांक 14 जून, 1968 (जैसे आज तक संशोधित) के कंडिका (पैरा) तीन में उप-कंडिका (vi) के स्थान पर निम्न उप-कंडिका प्रतिस्थापित की जाए :—

“स्नेहक (लुब्रिकेटिंग) तेलों, ग्रीज और विशिष्टियों (स्पेशलटीज) के अधिकतम विक्रय मूल्यों का निर्धारण—विशेष रूप से (क) देशीय या आयातित कच्चे तेल से भारत में तैयार किये गये/तैयार किये जाने वाले लूब-बेस स्टाक्स, और (ख) मिनरल टरपेन्टाइन आयल के मूल्यों का निर्धारण।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सारे मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी सचिव तथा सैन्य सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, वाणिज्य, निर्माण एवं विविध के महालेखाकार और केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति आम सूचना के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

माधव धी० राजवाड़े, संयुक्त सचिव

**स्वास्थ्य, एवं परिवार नियोजन, तथा निर्माण, आवास और****नगर विकास मंत्रालय****(निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1969

**संकल्प**

सं० 44/3/69-पी० 2—लोक लेखा समिति ने अपनी 34वीं रिपोर्ट के अनुच्छेद 1.25 में निम्न सिफारिश की है:—

“समिति यह सुझाव देती है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अपने प्रकाशनों के संबंध में पहले ही पर्याप्त प्रचार उन सम्भावित ग्राहकों के बीच करना चाहिये जिससे कि अपर्याप्त विक्री के कारण अनावश्यक स्टॉक को इकट्ठा होने से बचाया जा सके।”

उपयुक्त उपायों को करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक विभागीय समिति के गठन करने का निर्णय किया है।

2. समिति में निम्नलिखित होंगे:—

**(1) अध्यक्ष**

मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री।

**सदस्य**

(2) नियंत्रक मुद्रण, मुख्य नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय।

(3) प्रकाशन प्रबंधक, भारत सरकार प्रकाशन शाखा।

(4) अवर सचिव (मुद्रण), निर्माण, आवास तथा नगर-विकास विभाग।

(5) उप सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), डब्ल्यू० एण्ड ई० यूनिट।

(6) निदेशक, प्रकाशन प्रभाग, सूचना तथा प्रसार मंत्रालय।

(3) समिति की शर्तें ये होंगी:—

(i) प्रचार के सुधार के लिये उपयुक्त उपाय प्रस्तुत करना।

(ii) सरकारी प्रकाशनों के विक्री में वृद्धि के उपायों की सिफारिश करना।

(iii) अनावश्यक स्टॉक के संग्रह न होने देने के उपायों की सिफारिश करना।

4. समिति दिसम्बर, 1969 के अन्त तक अपना प्रतिवेदन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास तथा नगर-विकास विभाग) को प्रस्तुत करेगी।

5. समिति अपने कार्य करने के ढंग और अन्य मामलों की क्रियाविधि निश्चित करने में स्वतंत्र होगी।

6. मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय समिति को सचिवालय सम्बन्धी सहायता देने की व्यवस्था करेगा।

7. समिति में नियुक्त सभी सदस्य अपने-अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त इस समिति में कार्य करेंगे।

**आदेश**

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए।

आदेश हुआ कि संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

पं० प्रभाकर राव, संयुक्त सचिव

**(स्वास्थ्य विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 22 मई 1969

**संकल्प**

प सं० 1-3/68-आ० शि०—भारत सरकार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के मौलिक तथा व्यावहारिक विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारम्भ, मार्गदर्शन, विकास तथा समन्वय के लिए “भारतीय

चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद्" नामक एक स्वायत्त परिषद् का गठन करती है। सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अधीन केन्द्रीय परिषद् को एक समिति के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। इसका संचालन एक शासी निकाय द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

1. **अध्यक्ष**—केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (पदेन)
2. **उपाध्यक्ष**—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव (पदेन)।

#### सरकारी सदस्य

3. स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार (पदेन)।
4. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली (पदेन)।
5. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के महानिदेशक (पदेन)।
6. स्वास्थ्य विभाग के अवैतनिक होम्योपैथिक सलाहकार (पदेन)।
7. स्वास्थ्य विभाग, नई दिल्ली के विदेशी चिकित्सा पद्धति के सलाहकार (पदेन)।

#### संसद के प्रतिनिधि

8. और 9. लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसी सभा द्वारा चुने जाने वाले संसद के दो सदस्य।
10. राज्य सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिये, उसी सभा द्वारा चुना जाने वाला एक संसद सदस्य।

#### गैर-सरकारी सदस्य

11. से 14. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले आयुर्वेद के चार प्रतिष्ठित विद्वान
15. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला सिद्ध का एक प्रतिष्ठित विद्वान।
16. और 17. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले यूनानी के दो प्रतिष्ठित विद्वान।
18. और 19. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो प्रतिष्ठित योगी।
20. और 21. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले होम्योपैथी के दो प्रतिष्ठित विद्वान।
22. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के उप-कुलपति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक प्रतिनिधि।

23. स्नातकोत्तर स्वदेशी चिकित्सा पद्धति संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के उप-कुलपति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाने वाला एक प्रतिनिधि।

2. स्वास्थ्य विभाग के स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के सलाहकार शासी निकाय के सदस्य-सचिव तथा केन्द्रीय परिषद् के निदेशक होंगे।

#### प्रावेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

आर० एन० भट्टोकर, संयुक्त सचिव

#### खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 मई 1969

सं० 10-5/68-फेट—भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (अब खाद्य और कृषि) के संकल्प संख्या एफ० 16-72/47—नीति दिनांक 8 नवम्बर, 1948 के द्वारा निर्मित तथा संकल्प संख्या 10-1/65-फेट दिनांक 9 सितम्बर, 1966 द्वारा पुनर्गठित की गयी (अद्यतन संशोधित) राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन सम्पर्क समिति में रूरल पीपल्स इन्स्टीट्यूट, फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री तथा फारमर्स फोरम के प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान सदस्यों की कार्य-अवधि की समाप्ति पर, अधोलिखित व्यक्तियों को क्रमशः 1 जुलाई, 1968, 1 सितम्बर, 1968 तथा 1 अक्तूबर, 1968 से तीन वर्ष के लिये रूरल पीपल्स इन्स्टीट्यूट, फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री तथा फारमर्स फोरम के प्रतिनिधित्व के रूप में इस समिति के सदस्य मनोनीत किया गया है :—

1. श्री शरद पवार, विधान सभा सदस्य, वारामती, जिला पूना, (महाराष्ट्र)
2. श्री माधूबसिंह सोलंकी, विधान सभा सदस्य, स्वास्तिक सोसायटी 'बी', नवरंग पुरा, ग्रहमबाबा-9 (गुजरात)
3. श्री सौम्वर राजा मूपानार, विधान सभा सदस्य, मेलाकबिस्तलम, डाकखाना कबिस्तलम, पापनासम, थानाजायुर जिला, तामिल नाडु।
4. श्री ब्रजमोहन महन्ती, विधान सभा सदस्य, वकील, पुरी (उड़ीसा)
5. श्री योगेन शङ्कीया, विधान सभा सदस्य, वकील, जोरहाट (आसाम)
6. श्री बी० एस० अग्रवाल, 29 ए, बांसतस्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-7 (पश्चिम बंगाल)

रूरल पीपल्स इन्स्टीट्यूट के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर आफ कामर्स तथा इन्डस्ट्री के प्रतिनिधि

7. डा० डी० ए० मोले, मन्त्री, भारत कृषक फारमस फोरम, समाज, (फारमस फोरम, भारत) ए-1, भारत के प्रति-निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली-13 निधि

जगदीश चन्द्र माथुर, अपर सचिव

### (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 1969

सं० 26(1)/67-समन्वय(1)—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं 26(1)/66-समन्वय(1), दिनांक 6 अगस्त 1966 द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में गठित कृषि अनुसंधान की स्थायी समिति के सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि परिषद् की नियमावली के नियम 77 व 11(बी) में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 जनवरी, 1969 से उक्त स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे थे, परिषद् की उसी नियमावली के नियम 75 एवं नियम 77 व 10 के अन्तर्गत खाद्य व कृषि मंत्री द्वारा उक्त समिति के लिए उनकी सदस्यता के शेष काल के लिए अर्थात् 10 जनवरी, 1969 से 21 जुलाई, 1969 तक पुनः सदस्य मनोनीत किये गये हैं।

सं० 27(1)/67-समन्वय(1)—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 27(1)/66-समन्वय(1) दिनांक 8 अगस्त, 1966 द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में गठित पशु विज्ञान अनुसंधान की स्थायी समिति के सदस्य डा० सी० कृष्ण राव, जो पहले आन्ध्र प्रदेश के पशुपालन निदेशक तथा दुग्ध आयुक्त थे तथा अब इस मंत्रालय में भारत सरकार के पशु पालन आयुक्त हैं तथा जो परिषद् की नियमावली के नियम 77 तथा 11 (बी०) के अनुसार 3 फरवरी, 1969 से स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे थे, को परिषद् की उसी नियमावली के नियम 75 तथा नियम 77 व 10 के अन्तर्गत खाद्य एवं कृषि मंत्री द्वारा उक्त समिति में उनकी सदस्यता के शेष काल के लिए अर्थात् 3 फरवरी, 1969 से 30 जुलाई, 1969 तक पुनः सदस्य मनोनीत किया गया है।

सं० 29(1)/69-समन्वय-1—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की नियमावली के नियम 77 तथा नियम 11(बी०) के अन्तर्गत की गई व्यवस्थाओं के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 29(1)/66-समन्वय(1), दिनांक 18 अगस्त 1966 के द्वारा गठित परिषद् की कृषि शिक्षा स्थायी समिति के 15 अप्रैल, 1969 से सदस्य नहीं रहे।

- (1) श्री जी० के० चांदीरामानी, सचिव, भारत सरकार, शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (2) डा० एस० एन० दास गुप्ता, भूतपूर्व उप-कुलपति, कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी, (पश्चिम बंगाल)।
- (3) निदेशक/डीन, स्नातकोत्तर विद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
- (4) उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।

(5) डा० डी० एस० कोठारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

(6) डा० बी० डब्ल्यू० एक्स० पुनैया, डीन तथा कृषि अपर निदेशक, कृषि महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर।

(7) श्री ओ० पुल्ला रेड्डी, उप-कुलपति, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

(8) श्री डी० पी० सिंह, उप-कुलपति, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला नैनीताल।

(9) डा० बी० एम० के० सिन्हा, उप-कुलपति, बिहार-विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पी० एस० हरिहरन, अपर सचिव

### (खाद्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 मई, 1969

#### संकल्प

सं० 1-67/65-चीनी—भारत सरकार ने मई, 1951 में एक घी अपमिश्रण समिति नियुक्त की थी, इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि देश में तैयार किए जाने वाले सभी वनस्पति को कैरोटिन तेल सांद्रण की सहायता से नारंगी रंग किया जाना चाहिये ताकि घी में वनस्पति के मिलाने पर उसका पता लगाया जा सके। क्योंकि प्रस्तावित रंग सामग्री देश में उपलब्ध नहीं थी और उष्मा अथवा भण्डार में रखने पर उसकी क्षणभंगुरता के कारण भी भारत सरकार ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० वी०-44(9), दिनांक 27 अक्टूबर, 1952 में इस सिफारिश को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और वनस्पति के लिए उपयुक्त रंग सामग्री खोजने हेतु उस समय बहुत सी प्रयोगशालाओं में जो विभिन्न परीक्षण हो रहे थे उनके परिणाम जानने के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक समझा। जून, 1960 में सरकार ने अनुसंधान कार्य तेज करने और उनका समुचित ढंग से समन्वय करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे—

- (1) मुख्य निदेशक, शर्करा वनस्पति निदेशालय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली। संयोजक
- (2) डा० के० वेंकटरमन, निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुना। सदस्य
- (3) डा० बी० मुखर्जी, निदेशक, केन्द्रीय भोजन अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। सदस्य
- (4) डा० आर० एस० ठाकुर, उप मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (सेना) अनुसंधान तथा विकास संगठन, नई दिल्ली। सदस्य



- (5) डा० बी० सुब्रह्मण्यन,  
निदेशक, केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी  
अनुसन्धान संस्थान, मैसूर। मद्रस्य
- (6) डा० एन० एन० दम्नूर।  
प्रिंसिपल,  
डैरी विज्ञान कालेज,  
करनाल। मद्रस्य

2. भारत सरकार ने उपर्युक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार किया है। समिति के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष और उनकी सिफारिशों नीचे दी जाती हैं:-

(1) समिति ने बहुत अधिक रंगों की जांच की लेकिन इस उद्देश्य के लिए कोई भी रंग उपयुक्त नहीं पाया गया। यद्यपि वनस्पति से बने रंग आमतौर पर विपरीत नहीं होते हैं, लेकिन ये रंग किए हुए माल से या तो धूप में रखने, गरम करने अथवा वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग अरथ आदि जैसे सुगमता से मिलने वाले रसायनों के मिलाने से आसानी से उतारे जा सकते हैं। संश्लेषणात्मक रंग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक टिकाऊ होने पर भी खतरनाक है क्योंकि ये गरम करने पर टॉक्सिक एमाइन में विघटित हो जाते हैं।

(2) जिन विभिन्न वनस्पति रंगों का परीक्षण किया गया था उन में से केवल दो रंग अर्थात् रतनजोत और हल्दी रंग कुछ आशाजनक दिखायी दिए। तथापि, इन दोनों रंगों में वनस्पतियों से बने अन्य रंगों की तरह सामान्य न्यूनताएं पायी जाती हैं लेकिन रतनजोत की विषयता के बारे में सन्देह स्पष्ट नहीं हुए हैं। यह भी देश में उपलब्ध नहीं है लेकिन इसका भी आयात करना होगा। जहां तक हल्दी का सम्बन्ध है, इसका रंग शुद्ध घी की तरह है और इसका वनस्पति में रंग मिलाने के लिए प्रयोग करने पर घी में मिलावट रोकने की बजाए मिलावट करने में बढ़ावा मिल सकता है।

(3) रंग किए हुए माल से रतनजोत तथा हल्दी सहित वनस्पति-रंगों के सुगमता से उतर जाने के कारण वनस्पति घी में रंग मिलाने के लिए इनका प्रयोग घी में अपमिश्रण रोकने के प्रति केवल दिखावटी सुरक्षा ही होगी लेकिन इससे किसी भी हालत में ऐसे अपमिश्रण को कम करने की सम्भावना नहीं होगी। इस घी को विभिन्न भौतिक और रासायनिक उपचारों से रंग रहित करने की कोशिशों से वनस्पति और घी के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए एक अनिश्चित जोखिम पैदा होने की सम्भावना हो जाती है।

(4) समिति वनस्पति में रंग मिलाने के लिए कापरक्लोरोफिल के प्रयोग के सुझाव को निम्नलिखित बातों के कारण मानने में असमर्थ है (1) कापर का खाने के लिए प्रयोग करने पर इसका हानिकारक प्रभाव (2) इसके प्रयोग से माल में खटवास पैदा होने का खतरा (3) धूप में अथवा साधारण रंग मिलाने वाले तत्वों से उपचार करने पर इसकी धनभंगुरता और (4) इसमें मिलाया जाने वाला हरा रंग आंखों को प्रीतिकर न होने का कारण उपभोक्ता को स्वीकार्य नहीं होगा।

(5) खाद्य पदार्थों में संयोज्य के प्रयोग के बारे में, अत्यधिक विवशनापूर्ण परिस्थितियों में ऐसा करने को छोड़कर, इस देश तथा

विदेशों में सामान्य वैज्ञानिक राय विपरीत है। वनस्पति के सम्बन्ध में, तिल के तेल (शीशम आयल) द्वारा मिलाए गए अदृष्ट रंग से मिलावट का पता लगाने का वैकल्पिक तरीका उपलब्ध है।

(6) उपर्युक्त तथ्यों की दृष्टि में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वनस्पति में रंग मिलाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है और घी में वनस्पति के अपमिश्रण को रोकने अथवा बहुत ही कम करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने चाहियें। इस समय कानून के अधीन तिल के तेल (शीशम) के प्रयोग से वनस्पति में रंग मिलाने का तरीका इस उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन इस उपाय से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की दृष्टि से अन्यथा दृष्टिगत लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों की गयी हैं:-

(1) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि देश में तैयार किए जाने तथा बेचे जाने वाले सभी वनस्पति घी में तिल के तेल (शीशम आयल) की विहित मात्रा होनी चाहिये, और बोडोइन टेस्ट के अनुरूप हो और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्माता तथा विपणन दोनों अवस्थाओं पर वनस्पति के निरीक्षण तथा जांच-पड़ताल का काम तेज कर देना चाहिये।

(2) बाजार में विकने वाले घी के बड़े पैमाने पर नमूने लेने और नेगेटिव बोडोइन टेस्ट द्वारा जैसा प्रतिबिम्बित हो, वनस्पति में मिलावट न होने देने के लिए पग उठाने चाहियें।

(3) अपमिश्रण निवारण सम्बन्धी कानूनों को और अधिक सक्रियता से लागू किया जाना चाहिये।

(4) घी को छोटे डिब्बों में बेचने की तरजीह दी जानी चाहिये और उन पर एगमार्क सील लगी होनी चाहिये।

3. भारत सरकार ने समिति के उपर्युक्त निष्कर्षों पर सावधानी से विचार किया है। वनस्पति के लिए एक संतोषजनक रंग की कुछेक सारभूत अपेक्षाओं की परस्पर असंगतता के कारण वस्तुतः इस उद्देश्य के लिए किसी प्राकृतिक अथवा संश्लेषणात्मक रंग सामग्री के प्रयोग की सम्भावना नहीं रहती है। इन व्यावहारिक कठिनाइयों के अलावा, इस देश तथा विदेशों में खाद्य पदार्थों में संयोज्य के प्रयोग के बारे में वैज्ञानिक मतैक्य विपरीत है। इससे समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वनस्पति में रंग मिलाना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय है और इस दृष्टि से उद्देश्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने चाहियें। इस विचार की वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिपद ने भी पुष्टि की है।

घी अपमिश्रण समिति तथा विशेषज्ञ समिति के इस विषय पर पूर्व अध्ययनों के व्यापक सर्वेक्षण और कई वर्षों में किए गए विस्तृत स्थायी अनुसन्धानों पर आधारित निष्कर्षों और इस सम्बन्ध में सामान्य वैज्ञानिक राय को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार इस विचार और समिति के सुझाव से सहमत है कि वनस्पति के लिए रंग खोजने की बजाय घी में वनस्पति के अपमिश्रण को रोकने अथवा बहुत ही कम करने के लिए और अधिक वैज्ञानिक तरीके तैयार करने के प्रयत्न करने चाहियें। तथापि, सरकार उन संस्थानों तथा एजेंसियों के जिन्होंने इस विषय पर अनुसन्धान कार्य में सहयोग दिया है, यह कहने का विचार रखती है कि वे अपमिश्रण के लिए वनस्पति के प्रयोग की रोकथाम हेतु उपर्युक्त रंग सामग्री खोजने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखें।

सरकार भी समिति की इस सम्बन्ध में की गयी चारों सिफारिशों को स्वीकार करती है। इनका उद्देश्य तिल के तेल द्वारा वनस्पति में अदृष्ट रंग मिलाने के तरीके का और अधिक प्रभावी प्रयोग करना ताकि वनस्पति का घी में मिलावट के लिए दुरुपयोग करने पर इस का पता लगाया जा सके, यह तरीका पहले ही प्रयोग में लाया जाता है, और घी को मुख्यतः छोटे डिब्बों जिन पर एगमार्क सील लगी हो, कर ऐसे अपमिश्रण के अवसर बहुत ही कम करना है।

4. विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट सामान्य जानकारी के लिए अलग से प्रकाशित की जा रही है।

5. सरकार विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस विषय पर हुए पूर्व अनुसन्धानों का विशद सर्वेक्षण करने, काफी असें से इस अनिर्णीत प्रश्न पर अन्तिम निर्णय लेने के के योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अनुसन्धानों का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने तथा इस विषय पर अपने मूल्यवान सुझाव देने के लिए कष्टसाध्य प्रयत्न किए हैं।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय और योजना आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में छपवाया जाना चाहिये।

ए० एल० डायस, सचिव

### शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1969

सं० फा० 36-1/67-हि०-1—खैराती विन्यास अधिनियम, 1890 के विषय में और नागरी प्रचारिणी सभा न्यास, वाराणसी के विषय में,

यतः उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के सचिव द्वारा, जो नागरी प्रचारिणी सभा वियास न्यास, वाराणसी के प्रशासन में कार्य करने वाला व्यक्ति है, यह

आवेदन किया गया है कि एतदुपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उक्त न्यास के अभिधान के अधीन भारत के खैराती विन्यासों के कोषपाल में, भूतपूर्व संयुक्त प्रान्त राज्य की सरकार के शिक्षा विभाग की अधिसूचना सं० 4139/XV-336/1939 तारीख 5 जनवरी, 1940 में प्रकाशित उक्त न्यास के प्रशासन की स्कीम के पैरा 4 में निर्दिष्ट परिशिष्ट 'क' (पारितोषिक और पदक) परिशिष्ट 'ग' (नागरी प्रचारिणी सभा स्थायी निधि) और परिशिष्ट 'घ' (नागरी प्रचारिणी सभा प्रकाशन निधि) में अन्तर्निहित निबन्धनों पर न्यास में उपयोजित करने के लिए निहित किया जाए।

अतः अब खैराती विन्यास अधिनियम 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह आदेश देती है कि एतदुपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को पूर्वोक्त निबन्धनों पर न्यास में उपयोजित किए जाने के लिए भारत के खैराती विन्यासों के कोषपाल में निहित किया जाएगा।

### अनुसूची

1946 का 3 प्रतिशत संपरिवर्तन-उधार

परिशिष्ट 'क' (पारितोषिक और पदक) के लिए

सं० सी० ए० 242242	300.00 रु० के लिए
	योग 300.00 रु०

परिशिष्ट 'ग' (स्थायी निधि) के लिए

सं० सी० ए० 244297	10,000.00 रु० के लिए
सं० सी० ए० 243571	1,000.00 रु० के लिए
सं० सी० ए० 243572	1,000.00 रु० के लिए
सं० सी० ए० 243573	1,000.00 रु० के लिए

योग	13,000.00 रु० के लिए
-----	----------------------

परिशिष्ट 'घ' (प्रकाशन निधि) के लिए

सं० सी० ए० 244310	5,000.00 रु० के लिए
-------------------	---------------------

योग	5,000.00 रु०
-----	--------------

कुल योग	18,300.00 रु०
---------	---------------

निरंकार स्वरूप भटनागर, अनु सचिव

### PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th May 1969

No. 27-Pres./69.—The President is pleased to confer the "TERRITORIAL ARMY DECORATION" for meritorious service on the undermentioned commissioned officer of the Territorial Army :—

Major INDRA CHANDRA GHOSH, TA(M)-1012, Army Medical Corps.

The 28th May 1969

### CORRIGENDUM

No. 31-Pres./69.—In this Secretariat Notification No. 76-Pres./66, dated the 27th October, 1966, published in Part I,

Section 1 of the Gazette of India dated the 5th November, 1966 :

(a) On page 730

(i) Serial No. 52

For "NYA Naib Risaldar JARNAIL SINGH, 4 HORSE"

Read "1007292 Naib Risaldar JARNAIL SINGH, 4 HORSE (Posthumous)".

(ii) Serial No. 60

For "7015630 Dafadar JAGDISH LAL, 4 HORSE"

Read "7015630 Havildar JAGDISH LAL, EME"

## (b) On page 731

## (i) Serial No. 90

For "1024387 Sowar CHAINCHAL SINGH, 4 HORSE"

Read "1024387 Sowar CHAINCHAL SINGH, 4 HORSE (Posthumous)"

## (ii) Serial No. 183

Delete "3336858 Lance Havildar SAWINDER SINGH" and

Insert "1144079 Havildar SRINIVASA AMIN"

## (c) On page 735

## Serial No. 601

For "Lieutenant Colonel SANTI PRIYA GANGULI (IC-3652)"

Read "Lieutenant Colonel SANTI PRIYA GANGULI (IC-3653)".

V. J. MOORE, Dy. Secy. to the President

New Delhi, the 26th May 1969

No. 28-Pres./69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Chandra Dhar Bajpai,

Sub-Inspector of Police

Rampur, Uttar Pradesh.

(Officiating),

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 15/16th August, 1965, a burglary was committed in the shop of an Arms dealer in Civil Lines, Rampur, and a number of guns and cartridges were stolen. Police parties were sent out by all Police Stations and Outposts to search for the culprits. While one of those Police parties consisting of Shri C. D. Bajpai, another Sub-Inspector and two constables, was going in two cycle rikshaws, they noticed two persons lurking near the road in suspicious circumstances. Shri Bajpai challenged the suspects who at once fired on him and his party. One of the shots hit Shri Bajpai in the armpit, chest and forearm and seriously injured him. The other shot hit the rikshaw puller in the stomach and killed him on the spot. Undeterred by this murderous attack and his own injuries, Shri Bajpai led his men in an assault on the criminals. He himself grappled with one of them, and though he received further injuries, succeeded in arresting him. The other culprit was also arrested later.

Shri Chandra Dhar Bajpai displayed conspicuous gallantry in this encounter with armed criminals

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th August, 1965.

No. 29-Pres./69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

*Name of the officer and rank*

Shri Prahlad Ram,

Assistant Commandant,

3rd Battalion,

Rajasthan Armed Constabulary.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In September, 1965, Shri Prahlad Ram was deputed to re-capture the Indian post of Sanchu in the Bikaner Sector of Rajasthan which had been surreptitiously occupied by Pakistani forces after the cease-fire. Shri Prahlad Ram led an attack on the position in the early hours of 30th September,

1965. The Pakistani forces were well dug-in and were in an advantageous position. They had occupied the sand dunes which had precipitous slopes and made climbing very difficult during the assault. The Pakistani forces offered stiff resistance for nine hours but Shri Prahlad Ram launched several assaults in which he remained in the fore-front. After a hand to hand fight between Shri Prahlad Ram's Company and the Pakistani forces, the Pakistani troops were ultimately uprooted. Seven Pakistanis were taken prisoner and a large quantity of arms, ammunition and other equipment were captured.

Throughout, Shri Prahlad Ram placed himself in the fore-front of the assaulting waves and led his company to victory which was mainly achieved due to his outstanding bravery, devotion to duty and leadership of a higher order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th September, 1965.

The 26th May 1969

No. 30-Pres./69.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

*Name of the officer and rank*

Shri Sonam Wangdi Lama,

Inspector of Police,

District Enforcement Branch,

Darjeeling.

(Deceased)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th May, 1967, information was received that people were being organised in Barajharujote, P.S. Naxalbari, to commit acts of lawlessness in violation of Section 144 Cr.P.C. On receipt of this information O.C., Naxalbari P.S. left for the village with available officers and men. On seeing that the mob consisted on 300/400 persons who were armed with bows, arrows and other deadly weapons, reinforcement was sent for from the Naxalbari Police Station, which arrived under Inspector Shri Sonam Wangdi Lama. Shri Lama took charge of the situation and decided to give due warning to the mob to disperse before using any force against them. He also felt that advance of the police party might provoke the mob to violence. Thus to prevent bloodshed by not giving any provocation to the other side, the Police Inspector Shri Wangdi Lama advanced towards the mob followed by the O.C., Naxalbari P.S. and two other Sub-Inspectors none of whom was armed. The mob consisted of both men and women. On seeing the Inspector and his party advancing towards them, the male members of the crowd moved some distance away from there. The Inspector very calmly explained to the women-folk the undesirability of forming such assemblies in defiance of prohibitory orders and the crowd started dispersing. While this was happening, the male members were standing defiantly at their places. Shri Lama decided to approach and persuade them also to disperse peacefully. But as soon as he started advancing towards them, they began to shoot arrows at him. Before the main Police party could do anything to prevent the miscreants from committing such unprovoked act of brutality, Shri Lama received 4 arrow shots. He fell unconscious and later died in the hospital.

2. Shri Sonam Wangdi Lama displayed exceptional courage and skill in handling the mob unarmed and in a non-violent way, and his sincere bid to avoid bloodshed cost him his life.

3. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th May, 1967.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

## DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

## RESOLUTION

*New Delhi, the 23rd May 1969*

*No. F. 1-14/69-SW.3.*—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F. 1-16/69-SW-3, dated the 22nd April 1969, the Government of India are pleased to appoint the following as members in the General Body of the Central Social Welfare Board :—

1. Shrimati L. R. Biswas (Uttar Pradesh).
2. Shrimati Sanghamitra Chatterji (Tripura).
3. Shrimati Kusumtai Wankhede (Maharashtra).
4. Shrimati Indubala Sukhadia (Rajasthan).
5. Prof. Raja Ram Shastri (Social Welfare Administrator).
6. Dr. (Smt.) C. Parvathamma (Social Scientist).

## ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of the CSWB.
2. All State Governments/Union Territories.
3. All Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt./P.M.'s Sectt.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenue, New Delhi.
10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, CSWB, New Delhi (with 50 spare copies)

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. S. RAMDAS, Dy. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## CORRIGENDUM

*New Delhi-1, the 24th May, 1969.*

*No. 20/1/69-AIS(1)*—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 20/1/69-AIS(1) dated the 8th March, 1969 published in Part I Section I of the Gazette of India of 8th March, 1969, the following changes may be effected :—

Reference	For	Read
-----------	-----	------

## RULES

- |   |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| 1. Page 177, col. 2, last sub-para of rule 1, line 2. | for personality | for the personality |
| 2. Page 177, col. 2, last sub-para of rule 1, line 5. | preference      | preferences         |

## APPENDIX II

- |   |                                |                     |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 3. Page 181, col. 2, 2nd sub-para of para 1(b) line 3.              | following a subjects           | following subjects  |
| 4. Page 182, col. 2, item 14(b) under para (c)—additional subjects. | blank space against item 14(b) | 200                 |
| 5. Page 182, col. 2, Note II below para 1(b), line 6.               | Language & Script              | 'Language' 'Script' |

- |   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| 6. Page 184, col. 1, 5th sub-para of 11. Statistical Methods under 3. Statistics, line 2-3. | orthomials | orthogonal polynomials |
|---|------------|------------------------|

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 7. Page 184, col. 1, 2nd sub-para of III. Sampling distribution and statistical inference under 3. Statistics, lines 2 and 6. | <sup>12</sup> |  |
|---|---------------|--|

- |  |               |  |
|--|---------------|--|
| 8. Page 184, col. 1, 4th sub-para of III. Sampling distribution and statistical inference under 3. Statistics, line 3. | <sup>12</sup> |  |
|--|---------------|--|

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 9. Page 185, Col. 3, under 11 Assamese, Bengali etc. line 3. |  |  |
|--|--|--|

## APPENDIX III

- |  |                     |                             |
|--|---------------------|-----------------------------|
| 10. Page 195, col. 2, item (c) of paras 8-10, line 3.  | is                  | in                          |
| 11. Page 200, col. 1, Note 2 below item 15(m), line 3. | change              | chance                      |
| 12. Page 201, col. 2, 2nd sub-para of item 18, line 2. | Inter Organisations | Inter Service Organisations |

## APPENDIX IV

- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| 13. Page 203, Col. 2, para 1, line 3.    | like    | likely        |
| 14. Page 205, col. 1, para 10(h) line 2. | that is | that there is |
| 15. Page 205, col. 1, para 12, line 6.   | life    | like          |

A. N. BATABYAL, Dy. Secy.

## RESOLUTION

*New Delhi-1, the 26th May 1969*

*No. 8/2/69-H2.*—The Government of India are pleased to appoint Dr. V. K. R. V. Rao, Minister of Education and Youth Services and Shri Satyanarayan Sinha, Minister of Information, Broadcasting & Communications as members of the Kendriya Hindi Samiti constituted under this Ministry's Resolution No. 8/2/67-HSS dated the 5th September, 1967 in place of Shri Trigune Sen and Shri K. K. Shah respectively.

## ORDER

ORDERED that a copy this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Cabinet Sectt., Prime Minister's Sectt., Planning Commission, Comptroller & Auditor General, A.G.C.R., New Delhi, the Lok Sabha Sectt. and the Rajya Sabha Sectt.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. DHIR, Dy. Secy.

*New Delhi, the 28th May 1969*

*No. F. 5/22/69-CS(I).*—In the rules for the limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service to be held by the Union Public Service Commission in December, 1969, published under this Ministry's No. F. 5/22/69-CS(I), dated the 5th April 1969 in Part I, Section I of the Gazette of India dated the 5th April, 1969,—

(1) the second sub-para of Note 1 below rule 4 may be substituted by the following :—

"This, however, does not apply to an Assistant/Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants'/Stenographers' Grade, as the case may be".

(2) Rule 13 of the above named rules may be substituted by the following :—

"13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Service/Central Secretariat Stenographers' Service or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his department, or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistants'/Stenographers' Grade, as the case may be, will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to an Assistant/Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority."

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Petroleum)

### RESOLUTION

New Delhi, the 16th May 1969

No. 22(13)/68-OR.—Para 5 of the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) Resolution No. 22(13)/68-OR, dated the 20th April, 1968, as amended by Resolutions of even number, dated 30-7-68, 23-11-68 and 21-1-1969 shall be amended to read as follows :—

"5. The Commission will submit a report by the 31st of July, 1969".

### ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED further that a copy of the Resolution be communicated to All Ministries/Departments of Government of India, Government of Bihar and all other concerned.

M. V. RAJWADE, Jt. Secy.

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th May 1969

No. 9(1)/67-Salt.—In partial modification of this Ministry's Resolution of even No. dated the 14th June, 1968, Government hereby notifies that the Joint Secretary, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, concerned with the Administration of 'Salt' will be the Chairman, of the Central Advisory Board for Salt.

### ORDER

ORDERED that this corrigendum be communicated to all State Governments, all the Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Secretariat.

2. ORDERED also that this corrigendum be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

V. PRAKASH, Under Secy.

## COMPANY LAW BOARD

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 24th May 1969

### ORDER

No. 54/2/69-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri C. R. Mehta, Joint Director, Inspection, New Delhi, an Officer of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Company Affairs) for the purpose of the said section 209.

A. SOURJ RAJ, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Works, Housing and Urban Development)

### RESOLUTION

New Delhi, the 14th May 1969

No. 44/3/69-P.II.—The Public Accounts Committee have in para 1.25 of their 34th Report made the following recommendation :—

"The Committee suggest that the various Ministries and Departments should give adequate advance publicity to their respective publications amongst the likely customers in order to prevent accumulation of unnecessary stocks due to poor sales."

With a view to devising suitable measures, the Government of India have decided to constitute a departmental committee.

2. The Committee shall consist of :—

#### Chairman

(1) Chief Controller of Printing & Stationery.

#### Members

- (2) Controller of Printing, Office of the Chief Controller of Printing & Stationery.
- (3) Manager of Publications, Government of India, Publication Branch.
- (4) Under Secretary (Printing), Department of Works, Housing and Urban Development.
- (5) Deputy Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) W. & E. Unit.
- (6) Director, Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting.

3. The terms of reference of the Committee shall be :—

- (i) To evolve suitable measures for improving the publicity,
- (ii) To recommend measures to boost up sales of Government publications,
- (iii) To recommend measures to prevent accumulation of unnecessary stocks,

4. The Committee will submit its report to the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing & Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) by the end of December 1969.

5. The Committee will be free to lay down the method of its working and other procedural matters.

6. The secretarial assistance to the Committee will be provided by the Office of the Chief Controller of Printing and Stationery.

7. All the officers appointed on the Committee will do the work in addition to their normal duties.

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. PRABHAKAR RAO, Jt. Secy.

**Department of Health**  
**RESOLUTION**

*New Delhi, the 22nd May 1969*

*No. F. 1-3/68-AE.*—The Government of India are pleased to constitute an autonomous Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy to initiate, guide, develop and coordinate scientific research in the different aspects, fundamental and applied, of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy Systems of Medicine and Yoga Therapy. The Central Council shall be registered as a Society under the Societies' Registration Act, 1860. It shall be administered by a Governing Body consisting of the following Official and Non-Official Members :—

*President*

1. Union Minister for Health, Family Planning, Works, Housing and Urban Development (*ex-officio*).

*Vice-President*

2. Union Secretary/Additional Secretary for Health and Family Planning. (*ex-officio*).

*Official Members*

3. The Financial Adviser to the Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing and Urban Development (*ex-officio*).
4. Director General, Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi (*ex-officio*).
5. The Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi (*ex-officio*).
6. Honorary Adviser in Homoeopathy, Department of Health (*ex-officio*).
7. Adviser in Indian Systems of Medicine, Department of Health, New Delhi (*ex-officio*).

*Representatives of Parliament*

8. Two Members of Parliament representing the Lok &
9. Sabha to be elected by that Sabha.
10. One Member of Parliament representing the Rajya Sabha to be elected by that Sabha.

*Non-Official Members*

11. Four eminent Scholars of Ayurveda to be nominated to
14. by the Central Government.
15. One eminent Scholar of Siddha to be nominated by the Central Government.
16. Two eminent Scholars of Unani to be nominated by &
17. the Central Government.
18. Two eminent Yogis to be nominated by the Central &
19. Government.
20. Two eminent Scholars of Homoeopathy to be nominated &
21. nated by the Central Government.
22. One Representative of the Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, to be nominated by the Central Government, on the recommendation of the Vice-Chancellor of that University.
23. One Representative of the Post Graduate Institute of Indian Medicine, Banaras Hindu University, Varanasi, to be nominated by the Central Government on the recommendation of the Vice-Chancellor of that University.

2. The Adviser in Indian Systems of Medicine in the Department of Health, will be the Member-Secretary of the Governing Body and the Director of the Central Council.

**ORDER**

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY  
DEVELOPMENT AND CO-OPERATION**

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 12th May 1969*

*No. 10-5/68-FAIT.*—On the expiry of the terms of the present members representing the Rural Peoples' Interests, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and the Farmers' Forum on the National FAO Liaison Committee constituted in the late Ministry of Agriculture (Now Food and Agriculture) in Resolution No. F. 16-72/47-Policy, dated the 8th November, 1948 and reconstituted in Resolution No. 10-1/65-FAIT, dated the 9th September, 1966, as amended to date, the following have been nominated to serve on this Committee as representatives of the Rural Peoples' Interests, the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, and the Farmers' Forum, for a period of three years with effect from 1st July, 1968, 1st September, 1968 and 1st October, 1968, respectively :—

*Representative of the Rural Peoples' Interests.*

1. Shri Sharad Pawar, M.L.A.  
Baramati, Distt. Poona  
(Maharashtra).
2. Shri Madhavsinh Solanki, M.L.A.  
Swastik Society, 'B'  
Ahmedabad-9 (Gujarat).
3. Shri Soundararaja Mooppanar, M.L.A.,  
Melakabistalam, Kabistalam P.O.  
Papanasam, Thanjavur Dist.,  
Tamil Nadu.
4. Shri Braja Mohan Mohanty, M.L.A.,  
Advocate, Puri (Orissa).
5. Shri Jogen Saikia, M.L.A.,  
Advocate, Jorhat (Assam)

*Representative of the F.I.C.C. & I.*

6. Shri V.S. Aggarwal,  
29-A, Banstalla Street,  
Calcutta-7.

*Representative of the Farmers' Forum, India.*

7. Dr. D.A. Bholay,  
Secretary Bharat Krishak Samaj,  
(Farmers' Forum, India)  
A-1, Nizamuddin West,  
New Delhi-13.

J. C. MATHUR  
*Additional Secretary.*

**Indian Council of Agricultural Research**

*New Delhi, the 24th May 1969*

*No. 27(1)/67-CDN(I).*—Under the provisions of Rule 75 read with Rules 77 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, Dr. C. Krishna Rao, formerly Director of Animal Husbandry-cum-Milk Commissioner, Andhra Pradesh, and now Animal Husbandry Commissioner with the Government of India in this Ministry who ceased to be a member of the Standing Committee for Animal Sciences Research of the Council as constituted under this Ministry's Notification No. 27(1)/66-CDN(I), dated the 8th August, 1966, with effect from the 3rd February, 1969, under Rule 77 read with Rule 11(b) of these Rules, has been re-nominated by the Minister of Food and Agriculture as member of that Standing Committee for the unexpired portion of his term of membership of the Committee, viz. from the 3rd February, 1969 to the 30th July, 1969.

*No. 29(1)/69-CDN.I.*—Under the provisions of Rule 77 read with Rule 11(b) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research, the following persons have, with effect from the 15th April, 1969 ceased to be members of the Standing Committee for Agricultural Education as consti-

tuted under this Ministry's Notification No. 29(1)/66-CDN.I, dated the 18th August, 1966 :—

- (i) Shri G. K. Chandiramani, Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Youth Services, New Delhi.
- (ii) Dr. S. N. Das Gupta, former Vice-Chancellor, University of Kalyani, Kalyani (West Bengal).
- (iii) Director/Dean, Post-Graduate School Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.
- (iv) Deputy Director General, (Animal Sciences), Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
- (v) Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, New Delhi.
- (vi) Dr. B. W. X. Ponnalya, Dean and Additional Director of Agriculture, Agricultural College and Research Institute, Coimbatore.
- (vii) Shri O. Pulla Reddi, Vice-Chancellor, Andhra Pradesh Agricultural University, Hyderabad.
- (viii) Shri D. P. Singh, Vice-Chancellor, U.P. Agricultural University, Pantnagar, District Nainital.
- (ix) Dr. B. M. K. Sinha, Vice-Chancellor, University of Bihar, Muzaffarpur.

No. 26(1)/67-CDN(I).—Under the provisions of Rule 75 read with Rules 77 and 10 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research Dr. M. S. Swaminathan, Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, who ceased to be a member of the Standing Committee for Agricultural Research of the Council, as constituted under this Ministry's Notification No. 26(1)/66-CDN(I), dated the 6th August, 1966, with effect from the 10th January, 1969, under Rule 77 read with Rule 11(b) of these Rules, has been renominated by the Minister of Food and Agriculture as member of that Standing Committee for the unexpired portion of his term of membership of the Committee, viz. from the 10th January, 1969 to the 21st July, 1969.

P. S. HARIHARAN, Dy. Secy.

### Department of Food

#### RESOLUTION

New Delhi-1, the 12nd May 1969

No. 1-67/65-Sugar.—The Ghee Adulteration Committee appointed by the Government of India in May, 1951 recommended *inter alia* that all vanaspati produced in the country should be coloured orange with the help of carotene oil concentrate so as to enable detection of adulteration of ghee with vanaspati. Since the colouring medium proposed was not available indigenously and also because of its instability under heat or on storage, the Government of India, in the Ministry of Food and Agriculture Resolution No. SV-44(9), dated 27th October, 1952, expressed its inability to accept this recommendation and considered it necessary to wait for the results of the various experiments which were then in progress at a number of laboratories, for finding out a suitable colouring medium for vanaspati. In June, 1960, the Government set up an expert committee for intensifying the researches and coordinating them suitably. It included the following :—

#### Convenor

- (1) The Chief Director, Directorate of Sugar & Vanaspati, Ministry of Food & Agriculture, New Delhi.

#### Members

- (2) Dr. K. Venkataraman, Director, National Chemical Laboratory, Poona.
- (3) Dr. B. Mukerji, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow.
- (4) Dr. R. S. Thakur, Deputy Chief Scientific Officer (Army), Research and Development Organisation, New Delhi.
- (5) Dr. V. Subrahmanyam, Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore.
- (6) Dr. N. N. Dastur, Principal, Dairy Science College, Karnal.

2. The Government of India have considered the report submitted by the aforesaid Committee. The main conclusions arrived at, and recommendations made, by the Committee are given below :—

- (1) The Committee examined a large number of colours but found none of them suitable for the purpose. Although colours of vegetable origin are generally non-toxic, they are easily removable from the coloured product either by exposure to sunlight, heating or shaking with easily available chemicals like washing soda, bleaching earth etc. Synthetic colours, while being comparatively more stable are unsafe as they decompose into toxic amines on heating.
- (2) Of the different vegetable colours tested, only two viz., ratanjot and turmeric appeared to be somewhat promising. However, while both these colours share the general drawbacks common to other colours of vegetable origin, the doubts about the toxicity of ratanjot have not been clear. It is also not indigenously available but has to be imported. As regards turmeric, its colour is similar to that of pure ghee and its use for colouring vanaspati can conceivably result in promoting adulteration of ghee rather than preventing it.
- (3) Being easily removable from the coloured product, the use of vegetable colours, including ratanjot and turmeric, for colouring vanaspati would only give a superficial sense of security against adulteration of ghee, while in no way minimising the possibility of such adulteration. An additional health hazard is likely to arise for the consumers of vanaspati and ghee arising from the attempts at de-colourisation by various physical and chemical treatments.
- (4) The Committee is unable to accept the suggestion for the use of copper chlorophyll as a colouring agent for vanaspati in view of (i) the deleterious effect of copper when taken internally, (ii) the danger of rancidity being developed in the product as a result of such use, (iii) its instability to sunlight or treatment with common colouring agents and (iv) the green colour imparted by it, being not pleasing to the eye, would not be acceptable to the consumer.
- (5) The consensus of scientific opinion both in this country and abroad, is against the use of additives in foodstuffs, except under the most compelling circumstances. In the case of vanaspati, an alternative means of enabling detection of adulteration is available through the latent colour imparted by sesame oil.
- (6) In view of the foregoing, the Committee has come to the conclusion that colouring of vanaspati is neither practicable nor desirable and that alternative methods of preventing, or at least minimising, adulteration of ghee with vanaspati should be explored. The colouring of vanaspati with the use of sesame oil currently enforced under law should serve the purpose. But with a view to obtaining the best results out of this measure, and otherwise achieving the end in view, the following recommendations have been made :—
  - (i) It should be ensured that all vanaspati produced and marketed in the country contains the prescribed quantity of sesame oil, and responds to the Baudouin Test; and, to this end, the work of inspection and checking of vanaspati both at the manufacturer's and market stages, should be intensified.
  - (ii) Steps should be taken for large scale sampling of ghee sold in the markets and checking its freedom from adulteration with vanaspati as reflected by a negative Baudouin Test.
  - (iii) The anti-adulteration laws in force should be enforced more vigorously.
  - (iv) Ghee should be preferably marketed in small containers under AGMARK seal.

3. The Government of India have carefully considered the above conclusions of the Committee. The mutual incompatibility of some of the essential requirements of a satisfactory colour for vanaspati virtually rules out the use of any natural, or even synthetic colouring matter for this purpose. Apart from these practical difficulties, the consensus of scientific opinion, both in this country and abroad, is against the use of additives in foodstuffs. This has led the Committee to the further conclusion that colouring of vanaspati is neither practicable nor desirable, and that alternative methods should be explored for achieving the end in view. This view has also been endorsed by the Council of Scientific and Industrial Research.

Having regard to the findings of the Ghee Adulteration Committee, as well as those of the Expert Committee, based on an extensive survey, the earlier studies on the subject and detailed confirmatory researches carried out by it over a period of years, and the general scientific opinion in this regard, the Government of India agree with this view and concur with the suggestion made by the Committee that instead of a search for a colour for vanaspati, attempts should be made for more scientific methods of preventing, or at least minimising, the adulteration of ghee with vanaspati. Government, however, propose to ask the Institutes and Agencies which have collaborated in the research work on this subject to remain on the look-out for a suitable colouring medium for preventing the use of vanaspati for adulteration.

Government also accept all the four recommendations made by the Committee in this connection, which are aimed at a more effective use of the latent colourisation of vanaspati by sesame oil, as a means of detecting its misuse as an adulterant of ghee which is already in force; and the minimising of the chances of such adulteration by packing ghee preferentially in small containers with AGMARK seal.

4. The report submitted by the Expert Committee is being released separately for general information.

5. The Government wish to thank the members of the Expert Committee for their painstaking efforts in making an exhaustive survey of the earlier researches on the subject, and in chalking out and implementing a detailed programme of researches considered necessary for enabling a final decision to be arrived at on this long-standing issue, and for their valuable suggestions in this regard.

#### ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Administrations of Union Territories, all Ministries of the Government of India, the Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat and the Planning Commission.

ORDERED also that this Resolution should be published in the Gazette of India for general information.

A. L. DIAS, Secy.

#### MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 27th May 1969

No. F. 36-1/67-H.I.- In the matter of the Charitable Endowments Act, 1890, and in the matter of the Nagri Pracharini Sabha Trust, Varanasi.

Whereas an application has been made, through the Government of Uttar Pradesh, by the Secretary, Nagri Pracharini Sabha, Varanasi, being the person acting in the administration of the Nagri Pracharini Sabha Endowment Trust, Varanasi, that the securities specified in the Schedule hereto annexed be vested under the designation of the said Trust in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be applied in trust upon the terms contained in Appendix A (Prizes and Medals), Appendix C (Nagri Pracharini Sabha Permanent Fund) and Appendix D (Nagri Pracharini Sabha Publication Fund) referred to in paragraph 4 of the Scheme for the administration of the said Trust published in the notification of the Government of the former State of United Provinces, Education Department No. 4139/XV-336/1939, dated the 5th January, 1940.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Central Government hereby orders that the securities specified in the Schedule hereto annexed shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be applied in trust upon the terms aforesaid.

#### THE SCHEDULE

3% Conversion Loan of 1946

For Appendix A (Prizes and Medals)

No. CA 242242	For Rs. 300-00
Total Rs. 300-00	

For Appendix C (Permanent Fund)

No. CA 244297	For Rs. 10000-00
No. CA 243571	For Rs. 1000-00
No. CA 243572	For Rs. 1000-00
No. CA 243573	For Rs. 1000-00
Total Rs. 13000-00	

For Appendix D (Publication Fund)

No. CA 244310	For Rs. 5,000-00
Total Rs. 5000-00	
Grand Total Rs. 18300-00	

Z. S. BHATNAGAR, Under Secy.